करने की अनुमति देते हों। ए०बी०एफ०एस० एल० में निवेश से संबंधित मामले को कार्पोरेशन ने सतर्कता निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, को भेज दिया है।

Fencing of borders in Jammu region

478. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Centre is considering the proposal for fencing the international border along the Jammu frontier in view of the recent "spurt in infiltration" by the militants from Pakistan into the area;

(b) whether Government would accord priority to this proposal is view of the ISI threat to step UP violence in the Jammu region;

(c) the estimated cost of the project and the phases in which it shall be taken up; and

(d) what other effective measures are being taken to thwart Pakistan's ISI fanning trouble in the Jammu region and breaking its age old secular fabric?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRl RAJESH PILOT): (a) to (c) Yes, Sir. The total cost estimated for fencing (180 Km.) flood lighting (195.8 Kms) comes to about Rs. 71.76 crores. The work i$ expected to be completed by March, 1996.

(d) Government have initiated all necessary and appropriate steps to check smuggling of arms/ammunition including strengthening and deployment of para-military forces, their intensified patrolling, issue of sophisticated border surveillance equipments, gearing up State intelligence network and close coordination between various agencies, opening of new cbecok-posts and conducting of surprise checks, monitoring the activities of anti-social and anti-national elements etc.

बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान किया जाना

479. प्रो० राम बक्स सिंह वर्मा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों में विशेषकर गाजियाबाद में बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने तथा उन्हें वापस भेजने के लिए कोई योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ बंगलादेशी नागरिक उत्तर प्रदेश सहित देश के कुछ क्षेत्रों में चोरी-छिपे घुस आए हैं। ऐसे बंगलादेशी राष्ट्रिकों की संख्या का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि व चोरी छिपे प्रवेश करते हैं तथा स्थानीय जनसंख्या के साथ आसानी से मिल जाते हैं। सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों को इस आशय के स्थाई अनुदेश दिए गए हैं–कि वे अवैध बंगलादेशी नागरिकों का पता लगायें और उनको बंगलादेश लौटायें। इसके अलावा, सीमा सुरक्षा बल की गश्त बढ़ाने, इसके बाटरबिंग को मजबूत करने, विदेशी नागरिकों की रोकथाम (पी०आई० एफ०)/मोबाइल टास्क फोर्स (एम०टी०एफ०) नामक योजनाओं को मजबूत बनाने इत्यादि जैसे उपाय किए गए/किए जा रहे हैं ताकि घुसपैठ की कारगर रोकथाम की जा सके।

Report on Human Rights for the rear 1994

480- SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have taken note of the Amnestry Inter-national's report on Hunan Sifbtt